



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 16 मार्च, 1983/25 फाल्गुन, 1904

हिमाचल प्रदेश सरकार

श्रम एवम् रोजगार विभाग

अधिसूचनाये

शिमला-2, 4 मार्च, 1983

सं ०४-२/८२-श्रम.—आद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम के अंतर्गत २०) की धारा १ की उप-धारा (३) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, ऐसे आद्योगिक स्थापन, जिसमें पूर्वती बारह मासों में किसी कार्य-दिवस में पचास या उससे अधिक किन्तु एक सौ से कम व्यक्ति नियोजित हों, पर उक्त अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के प्रस्ताव को, कठित प्रस्ताव द्वारा सम्भाव्य प्रभावित व्यक्तियों से आक्षेप एवम् सुझाव आमन्वित करने हेतु सहर्ष अधिसूचित करते हैं। इस प्रस्ताव से प्रभावित कोई भी व्यक्ति अपने आक्षेप एवम् सुझाव श्रम-श्रायुक्त, हिमाचल प्रदेश शिमला-२ को इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर भेज सकता है जिसके पश्चात् आक्षेपों और सुझावों पर यदि कोई हो, विचार किया जाएगा।

शिमला-171002, 5 मार्च, 1983

सं ४-१७ ४१-एल ०५००ी ०.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १९४८ (1948 का अधिनियम संख्या 11) की धारा ४ की उपधारा (1) के खण्ड (III) के अध्ययन सहित धारा ३ की उपधारा (1) के खण्ड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे सलग अनुसूची के स्तम्भ (1) की तस्यानी प्रविष्टियों में यथा विनिर्दिष्ट खाद्य तथा पेय पदार्थ के नियोजनों में नियोजित अर्ध-कुशल तथा कुशल कर्मचारी मजदूर वर्गों को देय अनुसूची के स्तम्भ (2) और (3) में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी की दरों के संशोधन तथा निम्नलिखित कुछ इलाकों में प्रत्येक के आगे दिखाई गई राजि की बढ़ौतरी का राज्य सरकार का प्रस्ताव, उसमें सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सुचना हेतु, जैसा उक्त अधिनियम की धारा ५ की उप-धारा (1) के खण्ड (बी) के द्वारा अपेक्षित है, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा सुचित किया जाता है कि कथित प्रस्तावों पर इस अधिसूचना के राज्यत में प्रकाशित होने की तिथि से २ महीने के अवसान पर विचार किया जाएगा।

उक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में उक्त विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व प्राप्त हुए आक्षेपों या सुझावों जो अमायूक्त, हिमाचल प्रदेश, शिमला-२ द्वारा प्राप्त किये जाएंगे, पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

मासिक	
कुशल	रुपये 302.50
अर्ध कुशल	रुपये 275.00।

कुशल तथा अर्ध कुशल कर्मचारी की व्याख्या :

(क) कुशल कर्मचारी वह है जो दक्षता पूर्वक कार्य कर सके, काफी स्वतंत्रता से निर्णय बुद्धि का प्रयोग कर सके तथा त्रिम्मेवारी में अपने कर्तव्यों का पालन कर सके उसे उस व्यवसाय चिल्ह या उद्योग का जिम्म वह नियोजित किया गया हो पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होता चाहिये।

(ख) अर्ध कुशल कर्मचारी वह है जो सामान्यतः रोजमरा का एवं निश्चित स्वरूप का काम करता हो, जिसमें कि उसमें नियत बुद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो किन्तु उसमें मायेक्षित रूप से ऐसे छाट काम जो उसे सोंपे जायें उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हो और उनमें महत्वपूर्ण नियंत्रण द्वारा व्यक्तियों द्वारा किय जाते हों इस प्रकार उसका कार्य अत्र वंश वंशाये रोजमरा के कार्यों के करने तक हीं सीमित है।

गच्छाल महोदय निम्नलिखित स्थानों में प्रत्येक के मामते दिखाई गई बढ़ौतरी का भी आदेश देते हैं—

स्थान	बढ़ौतरी
-------	---------

- जिला लाहौल-सिप्ति, (किन्नौर), तहसील भरमोर तथा पांगी, जिला चम्बा
- मलाना प्राम पंचायत, जिला कुल्लू
- डोडगढ़ क्वार, तहसील गंहड़, जिला शिमला
- चोहर बंली, तहसील जोगिन्डनगढ़, जिला मण्डी
- वडा ब्रंगाल, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा

स्थान

1. तहसील गम्पुर तथा चौपाल, ज़िला शिमला	वडोतरी
2. तहसील आगंतुकी तथा निरमण, ज़िला कुल्लू	
3. ग्राम पंचायत मांगल, ज़िला सोलन	
4. चवासी इलाका तहसील करमोग, ज़िला मण्डी	
5. गरवी देहात तथा बटवारा, तहसील सुन्दरनगर ज़िला मण्डी	
6. छोटा चंगाल, तहसील गम्पुर, ज़िला कांगड़ा	
1. तहसील राहड़ी, ज़िला शिमला (डोडरा बवार को छोड़कर)	20 प्रतिशत
2. मव-तहसील शिलाई, रेणुका तहसील, ज़िला मिर्गमीर	
3. तहसील चुराह, ज़िला चम्बा	
4. इलाका मनाली तथा यूहजी पावंती तथा लाग वली बुनजार बचाक, कुल्लू, ज़िला कुल्लू	
5. कुट पंचायत तथा परगना बैलज, ज़िला चम्बा	
6. ज़माली बलाक तहसील चच्चोट, ज़िला मण्डी	
7. तहसील, करमोग, ज़िला मण्डी (इलाका चवासी को छोड़कर)	
1. उपरोक्त दर ममस्त दरों को मिलाकर है। 2. महिला तथा पुरुष मजदूरों को ममान मजदूरी दी जायेगी।	12½ प्रतिशत

शिमला-171002, 5 मार्च 19 3

मंस्या 8-17/81-एन्न० ई० पी०.—यतः हिमाचल प्रदेश के गज्यपाल, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम मंस्या 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (III) के प्रध्ययन महित धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (बी) द्वारा प्रदत्त व्यक्तियों का प्रयोग करते हुये इससे संलग्न अनुसूची के स्तरम् (1) की तत्त्वां प्रविष्टियों में यथा विनिर्दिष्ट शाल तथा गलीधा बुनाई के नियोजनों में नियोजित अर्ध कुण्ड, कुण्ड कर्मचारी मजदूर वर्गों को देय अनुसूची के स्तरम् (2) अथवा (3) में यथा विनिर्दिष्ट अन्यतम मजदूरी की दरों के संशोधन तथा निम्नलिखित कुछ इलाकों में प्रत्येक के अर्गे दिवार्ड गड़ राशि की बड़ोतरी का राज्य सरकार का प्रस्ताव, उसमें सम्बन्धित प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना हेतु, जैसा उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) के द्वारा अवेक्षित है, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा मुचित किया जाता है कि कथित प्रस्तावों पर इस अधिसूचना के गज्यपत्र में प्रकाशित होने की तिथि में 2 महीने के अवधान पर विचार किया जाएगा।

उक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में उक्त विनिर्दिष्ट अवधि के अवधान से पूर्व प्राप्त हुए आक्षेपों या मुझावों जो श्रमायुक्त, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002 द्वारा प्राप्त किये जाएंगे पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

कुण्ल	मासिक
रुपये	302.50
रुपये	275.00

कुण्ल तथा अर्ध कुण्ल कर्मचारी की व्याख्या :

(क) कुण्ल कर्मचारी वह है जो दक्षता पूर्वक कार्य कर सके, काफी स्वतंत्रता से निर्णय वृद्धि का प्रयोग कर सके तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। उसे उस व्यवसाय, शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना चाहिये।

(ख) अधिकृशल कर्मचारी वह है जो सामान्यतः रोजमर्रा का एवं निश्चित स्वरूप का काम करता हो जिसमें कि उससे उतनी निर्णय बढ़ि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो, किन्तु उससे सापेक्षित रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सीधे जायें उचित रूप से करन की अपेक्षा की जाती हो और उनमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा किए जाते हों, इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र बन्धे बंधाये रोजमर्रा के कार्य करने तक ही सीमित है।

राज्यपाल भहोदय निम्नलिखित स्थानों में प्रत्येक के सामने दिखाई गई बढ़ीतरी का भी आदेश देते हैं:—

स्थान

बढ़ीतरी

- जिला लाहौल-स्पिति, किल्लोर, तहसील भरमौर तथा तहसील पांगी, जिला चम्बा
- मलाना ग्राम पंचायत, जिला कुल्लू
- डोडरा क्वार, तहसील रोहड़, जिला शिमला
- चोहर वैली, तहसील जोगिंदर नगर, जिला मण्डी
- बड़ा बंगाल, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा

25 प्रतिशत

- तहसील रामपुर तथा चौपाल, जिला शिमला
- तहसील आनी तथा निरमण, जिला कुल्लू
- ग्राम पंचायत मांगल, जिला सोलन
- चवासी इलाका, तहसील करसोग, जिला मण्डी
- गरवी देहात तथा बटवारा तहसील मुन्दरनगर, जिला मण्डी
- छोटा बंगाल, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा

20 प्रतिशत

- तहसील रोहड़, जिला शिमला (डोडरा क्वार को छोड़कर)
- सब-तहसील शिलाई, रेणुका तहसील, जिला सिरमीर
- तहसील चुराह, जिला चम्बा
- इलाका मनाली तथा यूहजी पार्वती तथा लाघ वैली, बुनजार ब्लाक, कुल्लू, जिला कुल्लू
- कुट पंचायत तथा परगना वेलज, जिला चम्बा
- झज्जाली ब्लाक, तहसील चन्दोट, जिला मण्डी
- तहसील करसोग, जिला मण्डी (इलाका चवासी को छोड़ कर)

12½ प्रतिशत

नोट:— 1. उपरोक्त दर समस्त दरों को मिलाकर है।

2. महिला तथा पुरुष मजदूरों को समान मजदूरी दी जायेगी।

शिमला-171002, 5 मार्च, 1983

मंड्या 8-17/81-एल 0ई0पी0.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्या 11) का धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (iii) के अध्ययन सहित धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त अवित्यां का प्रयोग करते हुए इससे संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (1) की तस्यानी प्राविष्टियों में यथा विनिर्दिष्ट फौरेस्ट्री एवं टिम्बरिंग आप्रशन के नियोजनों में नियोजित अधिकृशल तथा कुशल कर्मचारी मजदूर वर्गों को देय अनुसूची के स्तम्भ (2) और (3) में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी

की दरों के संशोधन तथा निम्नलिखित कुछ इलाकों में प्रत्येक के आगे दिखाई गई राणि की बद्दीतरी का गज्य सरकार का प्रस्ताव, उम्में सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना हेतु, जैसा उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (बी) के द्वारा अपेक्षित है, एतद्वारा प्रकाशित विद्या जाता है और एतद्वारा उचित किया जाता है कि कथित प्रस्तावों पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की नियम में 2 महीने के अवधारण पर विचार किया जायेगा।

उक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में उक्त विर्तिवादी प्रवादी के अवधारण में पूर्व प्राप्त हुए आक्षेपों या सुझावों जो अप्राप्यकृत, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002 द्वारा प्राप्त किए जायेंगे, पर गज्य सरकार द्वारा विचार किया जायगा।

अनुसूची

कर्मचारी का वर्ग

दैनिक वेतन

वृक्षों का गिरान :

नापर छांगनी	10.30
पेनरज (गिरानी)	9.40

नाप्रिग तथा स्वार्गि तथा टिम्बर पालियंग :

1. इंसर (पचानी)	9.40
2. स्वार्यर (चरानी)	14.70
3. ब्लैक स्मिथ	12.90

करीज, स्टेकिंग तथा टिम्बर पालियंग वाई मैनुअल लेवर :

1. मजदूर फार कैरीज	9.40
2. मजदूर कुली लोर्डिंग अनलोर्डिंग आफ टिम्बर	9.40

कैरीज आफ टिम्बर वाई एरिया रोपवेज

1. सर्वेन मिस्ट्री-कम-सुपरवाईजर	14.70
2. स्पेन मिस्ट्री	12.90

कैरीज वाई वेट सलाइड (पक्की) नाली डाइव स्लाइड (पयर) वहाल दाय वहाल टिम्बर (प्लानिंग) :

1. मोहरी वाला मिस्ट्री	17.60
2. तर्ह	16.45
3. एसिस्टेन्ट मिस्ट्री (हैल्पर)	14.20
4. दरिया मैन	16.45
5. धालू	10.60
6. जगेदार	10.60

मकानाइज्ड लोग्रिग तथा टिम्बर एक्टूक्सन:

1. सर्वेनर	386.70
2. स्काई लाइन आप्रेटर	386.70

## कर्मचारी का वर्ग

## मासिक

3. ट्रक ड्राइवर	335.10
4. कम्परेशर ड्राइवर	282.45

## क्लैरिकल स्टाफ़:

1. मैनेजर	587.15
2. अकाउंटेंट	352.30
3. मूल्यी/टाईपिस्ट कलर्क	282.45

## स्वामिल वर्क्सः

1. वैड स्वा मिस्ट्री	386.70
2. सुपरवाइजर	375.55
3. हैड मिस्ट्री	386.70
4. वायरलैस ड्राइवर	386.70
5. ऐसिस्टेंट	293.55
6. पलेनर मिस्ट्री	293.55
7. कटरमैन	293.55
8. हैल्पर	282.45

## कथा एक्सट्रैक्शन

## दैनिक वेतन

1. वैलर तथा चौपर	9.40
2. कथा सुपरवाइजर/कथा प्रोसेसर	10.30

राज्य सरकार के निम्नलिखित इलाकों में प्रत्येक के आगे दिखाई गई राशि की बढ़ीतरी के प्रस्ताव को भ प्रकाशित किया जाता है:—

स्थान	बढ़ीतरी
1. जिनां लाहौल-स्पिति, किन्नौर, तहसील भरमौर तथा पांगी, ज़िला चम्बा 2. मलाना ग्राम पंचायत, ज़िला कुल्लू 3. डोडरा क्वार, तहसील रोहड़, ज़िला शिमला 4. चोहर वैली, तहसील जोगिन्द्रनगर, ज़िला मण्डा 5. बड़ा बंगाल, तहसील पालमपुर, ज़िला कांगड़ा	25 प्रतिशत
1. तहसील रामपुर तथा चौपाल, ज़िला शिमला 2. तहसील आनी तथा निरमण, ज़िला कुल्लू 3. ग्राम पंचायत मांगल, ज़िला सोलन 4. चंद्रासी इलाका, तहसील करसोग, ज़िला मण्डा 5. गरवी देहात तथा वटवारा, तहसील सुन्दरनगर 6. छोटा बंगाल, तहसील पालमपुर, ज़िला कांगड़ा	20 प्रतिशत

स्थान

बदौतरी

1. तहसील रोहड़, जिला शिमला (डोडरा बवार को छोड़कर)

2. सब तहसील शिंजाई, रेणुका, तहसील, जिला मिर्झीर

3. तहसील चुराह, जिला चम्बा

4. इलाका मनाली तथा पहाड़ी पार्वती तथा लाग बैली, बुनजार ब्लाक, कुल्लू, जिला कुल्लू } 12½ प्रतिशत

5. कुट पंचायत तथा परगना बल्ज, जिला चम्बा

6. झज्जाली ब्लाक, तहसील चच्चोट, जिला मण्डी

7. तहसील करसोग, जिला मण्डी (इलाका चवासी को छोड़कर)

नोट.—1. उपरोक्त दर मध्यस्त दरों को भिन्नाकर है।  
2. महिला तथा पुरुष मजदूरों को ममान मजदूरी दी जायेगी।

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित/-  
सचिव ।

### पंचायती राज विभाग

#### कार्यालय आदेश

शिमला-2, 5 मार्च, 1983

संख्या पी०सी००४८०-एच०-एच०४० (५)-५/८३.—जिला पंचायत अधिकारी, चम्बा, हिमाचल प्रदेश की सूचना पर श्री रतन चन्द बेडल, दिनांक ६-५-८२ से लगातार ग्राम पंचायत नैनीखड़ की मामिक बैठकों में अनुपमित रह रहे हैं;

और क्योंकि उक्त पंच, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2) (सी) के अन्तर्गत अपने पद पर बने नहीं रह सकते;

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, श्री रतन चन्द बेडल को हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 77 के अनुसार कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उन्हें ग्राम पंचायत नैनीखड़ के पंच पद से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2) (सी) के अन्तर्गत निष्कासित किया जाए। उनका उत्तर इस सम्बन्ध में इस नोटिस की प्राप्ति के एक मास के भीतर-भीतर जिला पंचायत अधिकारी, चम्बा के माध्यम से इस नियमालय को प्राप्त हो जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जायेगा कि वे अपने पक्ष में कुछ भी कहना नहीं चाहते।

हस्ताक्षरित/-  
अवर सचिव ।

### परिवहन विभाग

#### अधिसूचना

शिमला-2, 22 फरवरी, 1983

संख्या 6-८०/८१ (परिवहन).—मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 63 की उप-धारा (३बी) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर राज्य और दिल्ली तथा चण्डीगढ़

सभ राज्यों के बीच सार्वजनिक वाहनों पर संलग्न विशेष परस्पर अनुबन्ध में उल्लिखित तिथि से प्रभाव में लाने के लिए प्रकाशित करते हैं। उक्त अनुबन्ध करने का प्रस्ताव दिनांक 17 फरवरी, 1982 के असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इस विभाग की समसंबंधिक अधिसूचना दिनांक 12 जनवरी, 1982 के अधीन पहले प्रकाशित किया जा चुका है।

*Reciprocal agreement for public carriers between the States of Gujarat, Haryana, Madhya Pradesh, Maharashtra, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Delhi and Chandigarh.*

This agreement made this 30th day of October, one thousand nine hundred and eighty-two between the Governor of Gujarat of the One Part, the Governor of Haryana of the Second Part, the Governor of Madhya Pradesh of the Third Part, the Governor of Maharashtra of the Fourth Part, the Governor of Punjab of the Fifth Part, the Governor of Rajasthan of the Sixth Part, the Governor of Uttar Pradesh of the Seventh Part, the Governor of Himachal Pradesh of the Eighth Part, the Governor of Jammu and Kashmir of the Ninth Part, the President of India for and on behalf of the Union territory of Delhi of the Tenth Part and the President of India for and on behalf of the Union territory of Chandigarh of the Eleventh Part.

Whereas by an agreement dated the 5th September, 1981 between the Parties of the First, Second, Third, Fourth, Fifth, Sixth, Seventh, Eighth, Ninth, Tenth and Eleventh Parts, the said Parties entered into a reciprocal agreement with a view to encourage long distance inter-State transport of goods by and between the States of Gujarat, Haryana, Madhya Pradesh, Maharashtra, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Delhi and Chandigarh.

And whereas by mutual agreement, the Parties hereto have agreed to modify the terms and conditions of the said agreement dated the 5th September, 1981 and to enter into an agreement as herein contained, in partial modification of the existing agreement dated 5th September, 1981.

#### IT IS NOW AGREED BY AND BETWEEN THE ABOVE PARTIES AS FOLLOWS:

I. That this reciprocal agreement shall be in force from the 1st April, 1981 and shall be valid upto the 31st March, 1984. It may be renewed for such further period as may be mutually agreed to by all the signatories to this agreement. For reasons to be given in writing by any of the signatory States, this reciprocal agreement may be revoked on three months' notice. Such revocation shall, however, abridge and modify the operation of these agreements only in so far as it relates to the withdrawing States subject to the condition that permits already issued under this agreement will continue to be valid till the expiry of these permits irrespective of withdrawal by the State or States from this agreement.

II. The total number of vehicles for which composite permits shall be issued shall not exceed 450 for each of the States of Gujarat, Haryana, Madhya Pradesh, Maharashtra, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Delhi and 180 in the case of Chandigarh. The composite permits issued by the competent transport authority of each signatory State shall be valid on all National and State Highways chosen for operation. A list of these National and State Highways in each signatory State is annexed in the schedule hereto. The competent transport authority shall also issue each of such permit holders an authorisation in the form annexed to this agreement and such authorisation shall correspond to the period for which the advance payment has been received provided that the authorisation at one time shall not exceed a period of one year.

It shall, however, be open to any vehicle plying under such authorisation to deviate from the specified routes for a distance not exceeding 60 km. on either side of the specified routes.

III. If the composite permit holder fails to apply for renewal of authorisation for minimum number of States required to be chosen for operation under the agreement within the period of one month from the date of expiry of previous authorisation, his permit shall be liable to be cancelled.

III. (i) Each applicant for a composite permit shall have to choose a minimum of three States *i.e.* home State and any two other States out of the remaining ten for operation with effect from the date of this agreement.

(ii) If a composite permit holder chooses to exclude a contiguous State for operation through which his vehicle must have to pass to reach any other State chosen for operation within the scheme, the holder of the permit shall have to pay full taxes to the 'transit' State.

(iii) A composite permit holder of a State shall be allowed to operate in any other State, separately covered under a bilateral agreement, but the same vehicle will not be allowed to be used both for the composite permit scheme as also the bilateral agreement scheme, in the same State.

(iv) An option once exercised by a composite permit holder will not be allowed to be changed before a period of one year.

(v) Notwithstanding that a composite permit holder will not be allowed the option once exercised to be changed before a period of one year as per sub-clause (iv) above, the composite permit holder may, at his option, come up at any time during the course of the year for addition of State or States covered by the zone in his authorisation, provided he is agreeable to pay full taxes for the year. During the period of authorisation once granted, no deletion of State or States once opted shall be allowed.

IV. A public carrier operating under this agreement shall be free to operate without restriction of routes in the home State whereas while operating in any area outside the home State such a public carrier shall not pick up or set down goods between any two points lying wholly within the jurisdiction of the reciprocating State *i.e.* in such cases vehicles shall be prohibited from carrying any intra-State business.

V. A public carrier operating under this agreement shall be subject to the following limitations and restrictions:—

(1) No vehicle may be authorised under this agreement which—

(a) is more than 4 years old on the date of grant of the authorisation and is more than 9 years old at any time;

(b) does not carry the prescribed markings and distinguishing particulars and is not painted in the prescribed colour scheme as provided in the schedule annexed herewith;

(c) is not fitted with body in conformity with the pattern as prescribed in the schedule annexed herewith.

(2) A public carrier plying under this agreement shall at all times carry a bill of lading in the form prescribed in the schedule annexed. Carriage of goods not in conformity with the declaration in the bill of lading shall be construed as infringement of the condition of the permit making the permit holder liable under section 60 of the Motor Vehicles Act.

(3) Such vehicles shall conform to and comply with all provisions of the Motor Vehicles Act as well as the provisions of the Motor Vehicles Rules framed by the home State

subject to such restrictions as may be imposed by the State Governments from time to time under the provisions of the Motor Vehicles Act, 1939.

- (4) The certificate of fitness of such a vehicle shall be liable to be suspended or cancelled by the competent authority of the home State if it is found to be not in conformity with the provisions relating to fitness, colour and body specifications as detailed in the schedule annexed hereto.
- (5) Any authorisation holder plying under this agreement shall file a quarterly return in regard to such vehicle in the form prescribed as detailed in the schedule annexed hereto in quadruplicate to the Secretary of the State Transport Authority of the home State who, in turn, shall furnish copies thereof to the Secretaries, State Transport Authorities of the other signatory States.
- (6) Such a vehicle shall at all times carry—
  - (a) A valid certificate of fitness;
  - (b) A certificate of registration; and
  - (c) Bill/Bills of lading covering goods actually carried in the vehicle at the moment.
- (7) Such a vehicle shall at all times carry valid authorisation in the form as detailed in the schedule annexed granted under this agreement and issued under the signature and seal of the competent transport authority of the home State.

VI. A vehicle plying under authorisation issued under this special agreement may be stopped and inspected for the purpose of enforcement of the provisions of this agreement by an officer of the rank of Assistant Inspector of Motor Vehicles or Sub-Inspector of Police or any other officer whose rank is mutually agreed upon by the signatory States. Such an Inspecting Officer shall issue a check report in triplicate, one copy of which shall be served on the person in-charge of the vehicle, the second shall be sent to the competent transport authority of the home State and third copy sent to the competent transport authority of the State concerned. The competent transport authority of home State, on receipt of the copy of the check report, may take such action as he may deem fit.

VII. (1) A composite permit holder plying under authorisation shall be liable to pay as under:—

- (a) Motor Vehicles Tax and the Goods Tax obtaining in the home State.
- (b) A sum of Rs. 500/- per annum in lieu of taxes mentioned in clause (a) above to Delhi in case it is chosen for operation, a sum of Rs. 150/- per annum in lieu of taxes mentioned in clause (a) above to Chandigarh in case it is chosen for operation and a sum of Rs. 1000/- per annum in lieu of taxes mentioned in clause (a) above to each of the remaining States, other than the home State, chosen by the operator. This sum shall be paid in advance by a crossed bank draft on or before the 15th of March, every year (irrespective of the R.L.W. and P.L.W. of the vehicle). For this purpose, all signatory States shall make suitable provisions in their taxation laws. Each signatory State shall designate a competent authority for the purpose of receiving the amount mentioned above on behalf of other States, which shall thereafter be transferred to the respective States. Such competent authority shall stamp and endorse the authorisation to that effect. Any vehicle plying under such an authorisation in the absence of such a valid endorsement shall be deemed to be plying in contravention of the condition of the permit and shall be liable to suspension and cancellation of the permit under section 60 of the Motor Vehicles Act.

The sums mentioned above will not be inclusive of municipal levies, such as octroi etc. and composite permit holder will be liable to pay them separately.

(2) Notwithstanding that the amount is required to be paid for the whole year in advance as per sub-clause (1) above the owner of the vehicle may, at his option, pay in two equal instalments, the first on or before 15th March (every year) for the period April—September and the second instalment on or before 15th September (of the current financial year) for the period October—March and obtain endorsement of having paid this amount from the competent authority of the home State in certificate specified in Annexure II.

(2A) A composite permit holder shall be required to pay a fee of Rs. 300/- per year per vehicle for grant of an authorisation irrespective of the number of States chosen for operation. This sum shall be paid in advance in full irrespective of whether authorisation is granted at the commencement of financial year or after the commencement thereof by bank draft to the competent authority of the home State who will retain the amount.

(3) If the vehicle covered by the authorisation is kept under non-use for a period/periods during the validity of the authorisation, no refund of amount paid under sub-clause (1), (2), (2A) and (6) for that period/periods will be allowed.

(4) If the initial authorisation is granted at any time after the first quarter of the financial year, the tax/amount shall be assessed on pro-rata basis for the remaining quarters of the financial year including the quarter in which the authorisation is granted. For this purpose, a quarter shall be taken as a unit and not months and days, provided that this relief shall not be admissible for subsequent authorisations.

(5) If the vehicles covered by the authorisation is sought to be replaced by another suitable vehicle after prior permission of the authority which originally granted the permit, the registration mark of the replaced vehicle may be noted by the home State Transport Authority in the authorisation and the tax/amount already paid shall be deemed to have been paid for the replaced vehicle for the period following the date on which vehicle is replaced.

(6) If an operator does not pay the composite tax within the prescribed period, he shall be liable to pay, in addition to the composite tax of Rs. 1000/-, an additional sum of Rs. 100/- per month or part thereof for each of the States covered by the scheme in respect of which payment is delayed. The said amount shall be payable through crossed bank draft in the name of the designated authority of State concerned and shall be sent to the State concerned as and when received. The operator would also be required to pay any other penalty for delay in payment of home State taxes that might be imposed by the State under its own rules.

VIIA. If a composite permit holder proposes to replace his vehicle by another vehicle, the latter vehicle shall be not more than four years old on the date of application for such replacement.

VIII. The competent authority of the home State shall receive the amount on behalf of the other States as the case may be in the form of crossed bank drafts. These drafts shall be made payable in the name of the designated authority of the State concerned and shall be sent by the home State to the State concerned as and when received along with a statement showing the details of the vehicle number, crossed bank draft number, and date and amount, period for which paid etc.

IX. (A) For the implementation of this agreement, the S.T.A. or the R.T.A., as the case may be of the State shall issue composite permits for the inter-State routes or areas, as the case may be, covered by this reciprocal agreement for any three or more of the signatory States; such a composite permit holder shall have the benefit of rule framed under section 68(2)(hh) read with section 63(1) of the M.V. Act, 1939 referred to in para below and the competent authority shall furnish copies of these composite permits (Part B only) to other signatory States within 30 days of issue.

(B) Further, all the signatory States shall frame a suitable rule under Sec. 68(2)(iii) read with Sec. 63(1) to provide that the composite permit so granted shall be valid without counter-signature in the areas of the other signatory States and the Secretary of the State Transport Authority or the competent authority, as the case may be, of the home State shall issue an authorisation in the form prescribed in the schedule.

(C) Such composite permits shall be valid in all the signatory States other than the home State on all National and State Highways of each State as specified in permit. A list of these Highways is annexed in the schedule hereto. The composite permits shall also be valid on such other National Highways and State Highways as may be notified from time to time by the Union Government or the State Governments concerned and which are endorsed on the permit.

X. In the case of the transfer of the composite permits, the authorisation granted under this agreement shall not be transferable except with the approval of the Secretary of the State Transport Authority or the competent authority of the home State as the case may be.

XI. In this agreement, the term 'home State' means the State in the territory of which the composite permit under section 56 has been granted and authorisation therefor is issued under this agreement.

XII. For the purpose of this agreement, the term "year" shall be deemed to be a financial year.

XIII. For the purpose of this agreement, each of eleven parties hereto shall be deemed to be a "State".

Sd/-  
Secretary to Govt. of Gujarat,  
Home Department, Gandhinagar.

Sd/-  
Secretary to Govt. of Haryana,  
Transport Department, Chandigarh.

Sd/-  
Secretary to Govt. of Madhya Pradesh,  
Home Department, Bhopal.

Sd/-  
Deputy Secretary to Govt. of Maharashtra,  
Home Department, Bombay.

Sd/- RAJINDER SINGH,  
Secretary to Govt. of Punjab,  
Transport Department, Chandigarh.

Sd/- V. I. RAJAGOPAL,  
Secretary to Govt. of Rajasthan,  
Home (Tpt.) Department, Jaipur.

Sd/- S. K. TRIPATHI,  
Secretary to Govt. of Uttar Pradesh,  
Transport Department, Lucknow.

Sd/-  
Secretary to Govt. of Himachal Pradesh,  
Transport Department, Simla.

Sd/-  
Director General Transport, Govt. of J & K,  
Transport Department, Jammu.

Sd/-  
Special Secretary (Transport),  
Delhi Administration, Delhi.

Sd/-  
Transport Secretary,  
Chandigarh Administration,  
Chandigarh.

#### ANNEXURE I

#### AUTHORISATION UNDER SPECIAL RECIPROCAL AGREEMENT

1. Name in full (starting with surname and complete address)
2. Registration mark

No.

3. Engine No.	..		
4. Chassis No.	..		
5. Original Permit No.	..		
6. Permit issuing authority	..		
7. Make	..		
8. Year of manufacture	..		
9. R. L. W.	..		
10. U. L. W.	..		
11. Period of validity of authorisation	..	From	To
12. Valid for the States:	..		
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
		10.	

(Signature of the competent authority)

(Seal of the competent authority)

**CERTIFICATE OF PAYMENT OF TAX UNDER SPECIAL RECIPROCAL AGREEMENT**

*Rate of Annual Tax*

Name of the State	Amount paid	Particulars of bank draft and date	Date of payment	Period for which paid	Registration No. of the vehicle
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

(Signature and seal of the authority).

## ABSTRACT OF CONDITIONS OF COMPOSITE PERMIT

1. This authorises the operation of the vehicle on all the National and State Highways in the signatory States chosen for operation other than the home State. A list of National and State Highways is annexed hereto. The vehicles shall also be valid on such other National and State Highways as may be notified from time to time by the Union Government or the State Governments concerned and which are endorsed on the permits.

The vehicle shall also be authorised to deviate upto 60 km. on either side of the specified routes.

2. While operating in any area outside the home State such a public carrier shall not pick up or set down goods between any two points plying wholly within the jurisdiction of the reciprocating State i.e. in such cases vehicles shall be prohibited from carrying any intra-State business.

3. The vehicle shall be painted in orange colour with a broad white border and a board showing the following inscription in white letters on black background shall be carried prominently above the "PUBLIC CARRIER" board:

*Inscription;* PERMIT UNDER SPECIAL RECIPROCAL AGREEMENT

\*Valid in Gujarat, Haryana, Madhya Pradesh, Maharashtra, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Delhi and Chandigarh.

(\*Strike out the name of the State not applicable).

4. The vehicle shall at all times carry the bill/bills of lading (in the manner directed by the S.T.A., Home State, covering the goods in the vehicle).

5. Quarterly return shall be submitted to the Secretary, State Transport Authority of the home State.

6. The vehicle shall conform and comply with all the provisions of Motor Vehicles Act as well as the provisions of the Motor Vehicles Rules framed by the home State, subject to such conditions as may be imposed by the State Governments from time to time under the provisions of the Motor Vehicles Act, 1939.

7. The vehicle shall at all times carry a valid certificate of fitness, certificate of registration and insurance, the original permit documents and the authorisation issued under this agreement.

8. A composite permit holder plying under such an authorisation shall be liable to pay as under:—

(a) Motor Vehicles Tax and Goods Tax obtaining in the home State.

(b) A sum of Rs. 500/- per annum in lieu of taxes mentioned in clause (a) above to Delhi in case it is opted for operation, a sum of Rs. 150/- per annum in lieu of taxes mentioned in clause (a) above to Chandigarh in case it is opted for operation and a sum of Rs. 1000/- per annum in lieu of taxes mentioned in clause (a) above to each of the remaining States of his option other than the home State.

The sums mentioned above shall be payable in advance by crossed bank draft(s) on or before the 15th of March, every year. The competent transport authority of the home State on collection of the amount stamp and endorse the authorisation to that effect.

The composite permit holder may, at his option, pay the annual tax/amount in two instalments, the first on or before 15th March (every year) for the period April—September and the second instalment on or before 15th September (of the current financial year) for the period October—March.

8A. Composite permit holder shall be required to pay a fee of Rs. 300/- per year per vehicle for grant of an authorisation irrespective of the number of States chosen for operation. This sum shall be paid in advance by bank draft to the competent authority of the home State who will retain the amount.

9. (i) Each applicant for a composite permit shall have to choose a minimum of three States *i.e.* the home State and any two other States out of the remaining ten for operation, with effect from the date of this agreement.

(ii) If a composite permit holder chooses to exclude a contiguous State for operation through which his vehicle must have to pass to reach any other State chosen for operation within the scheme, the holder of the permit shall have to pay full taxes to the "Transit State".

(iii) An option once exercised by a composite permit holder will not be allowed to be changed before a period of one year.

(iv) Notwithstanding that a composite permit holder will not be allowed the option once exercised to be changed before a period of one year as per condition 9(iii) above, the composite permit holder may, at his option, come up at any time during the course of the year for addition of State or States covered by the Zone in his authorisation, provided he is agreeable to pay full taxes for the year, During the period of authorisation once granted, no deletion of State or States, once opted shall be allowed.

10. If a composite permit holder fails to apply for renewal of authorisation for minimum number of States required to be chosen for operation under the agreement within a period of one month from the date of expiry of previous authorisation, his permit shall be liable to be cancelled.

11. If an operator does not pay the composite tax within the prescribed period, he shall be liable to pay, in addition to the composite tax of Rs. 1000/- an additional sum of Rs. 100/- per month or part thereof for each of the States covered by the scheme in respect of which payment is delayed. The said amount shall be payable through crossed bank draft in the name of the designated authority of the State concerned and shall be sent to the State concerned as and when received. The operator would also be required to pay any other penalty for delay in payment of home State taxes that might be imposed by that State under its own rules.

12. If a composite permit holder proposed to replace his vehicle by another vehicle, the latter vehicle shall be not more than four years old on the date of application for such replacement.

### ANNEXURE III

#### BILL OF LADING

Name and address of the permit holder.

Truck No.

Bill No.  
Date

Name of the consignors

Name of the consignee

Destination

No. of articles	Description of goods	Cwt. B. Mds. kg.	Freight charge paid		Freight charge to pay	Total	Bill No. ....
			Rs.	P.			Date, .....
							Received, .....
							Package from, .....

Truck No.
Signature

Signature of the consignor.

(Signature of the carrier).

At carrier's risk.

At owner's risk.

Value of the goods Rs. ....

Delivery at.....

**Note.**—The bill of lading will be prepared in the proforma given above and will be in quadruplicate, the original (white) to be carried in the vehicle, the duplicate (light green) for consignor, the triplicate (pink) for the consignee and the fourth copy (creem yellow) for record of the permit holder.

## ANNEXURE IV

## QUARTERLY RETURN

1. Name of the operator and address .....
2. Registration mark of vehicle .....
3. Composite permit No. ....

SUMMARY OF TRIPS MADE DURING THE QUARTER

Month	Total distance covered in the States of					Punjab
	Gujarat	Haryana	Madhya Pradesh	Maharashtra		
1	2	3	4	5	6	

Rajasthan	U. P.	H. P.	J & K	Delhi	Chandigarh	Total distance of operation	Remarks
							14
7	8	9	10	11	12	13	

Date.....

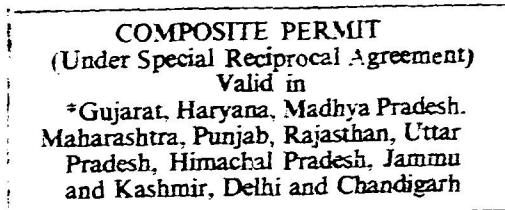
Signature of the permit holder.

Note.—In the remarks column, state reasons for low or high running in any particular State or States and any other points which caused low operation.

ANNEXURE V

SPECIFICATION OF THE COLOUR SCHEME AND SPECIAL MARKINGS TO BE CARRIED ON THE VEHICLES AND THE CONSTRUCTION OF THE VEHICLE

1. The vehicle shall be painted in orange colour with broad (30 cm.) white borders. The words "W.Z." in big letters will be inscribed on two sides of the vehicle.
2. A board with the following inscription with white letters on black background shall also be carried so as to be clearly visible above the "PUBLIC CARRIER" board:—



\*Strike out the name of the States not applicable.

शिमला-2, 7 मार्च, 1983

संख्या 6-41/82-(परिवहन).—मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 127-B की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राज्य पुलिस के यातायात पक्ष में नियुक्त पुलिस उपनिरीक्षक और उससे ऊपर के पदवाले अधिकारियों को कथित उपधारा में प्रसाधित अपराधों का शमन करने हेतु सहर्ष प्राधिकृत करते हैं और निदेश देते हैं कि शमन अतेर प्रस्त अपराधों हेतु विहित किए गए अधिकतम जुर्माने की 50 प्रतिशत दर से कम नहीं होगा।

आरो के 0 आनन्द,  
आयुक्त एवं सचिव ।

[In pursuance of clause (3) of article 348 of Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to publish the English Text of Notification No. 6-41/82 (Parivahan), dated the 7th March, 1983 for the general information of the public.]

## TRANSPORT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

No. 6-41/82 (Parivahan).—In exercise of the powers under sub-section (1) of section 127-B of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to authorise the officers of the rank of Sub-Inspector of Police and above posted in the Traffic Wing of the Himachal Pradesh State Police to compound offences enumerated in the said sub-section and direct that the compounding would not be at the rate less than 50% of the maximum fine prescribed in respect of the offences involved.

R. K. ANAND,  
Commissioner-cum-Secretary.